

Published by:				
NEERAJ PUBLICATIONS				
Sales Office : 1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 E-mail: info@neerajignoubooks.com	006			
Website: www.neerajignoubooks.com				
Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only	Typesetting by: Competent Computers	Printed at: Novelty Printer		
<b>Notes:</b> 1. For the best & upto-date study & results, please prefer the recomm	nended textbooks/study ma	aterial only.		
<ol> <li>This book is just a Guide Book/Reference Book published by NE syllabus by a particular Board /University.</li> </ol>	· · · ·			
<ol> <li>The information and data etc. given in this Book are from the best complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of In Board/University.</li> </ol>				
4. Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.				
5. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can for the price of the Book.	•	· ·		
<ol> <li>If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.</li> </ol>	-			
<ol> <li>The number of questions in NEERAJ study materials are indicati paper.</li> </ol>				
<ol> <li>Question Paper and their answers given in this Book provide you and is prepared based on the memory only. However, the actual Que distribution of marks and their level of difficulty.</li> </ol>	estion Paper might somewha	t vary in its contents,		
9. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.				
10. Subject to Delhi Jurisdiction only.				
© Reserved with the Publishers only.				
<b>Spl. Note:</b> This book or part thereof cannot be translated or reprodu- without the written permission of the publishers.	uced in any form (except for	review or criticism)		
How to get Books by I	Post (V.P.F	<b>P.</b> ]?		
If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then p Website www.neerajignoubooks.com. You may also avail the 'Special Di. (Time of Your Order).				
To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website <b>www.neerajignoubooks.com.</b> No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges. We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).				
NEERAJ PUBLICATIONS				
(Publishers of Educational Books)				
(An ISO 9001 : 2008 Certified Company) <b>1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006</b>				
Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501				
E-mail: info@neerajignoubooks.com Website:	www.neerajigno	oubooks.com		

# CONTENTS

# वित्तीय प्रशासन

(FINANCIAL ADMINISTRATION)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2017 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1
Question Paper—December, 2016 (Solved)	1
Question Paper—June, 2016 (Solved)	1
Question Paper—December, 2015 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2015 (Solved)	1
Question Paper—June, 2014 (Solved)	1
Question Paper—June, 2013 (Solved)	1
Question Paper—June, 2012 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2011 (Solved)	1
Question Paper—June, 2010 (Solved)	1-2

S.No.

# Chapterwise Reference Book

Page

1.	वित्तीय प्रशासन की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र ( Nature and Scope of Financial Administration )	1
2.	वित्तीय प्रशासन के उद्देश्य और सिद्धान्त ( Objectives and Principles of Financial Administration )	8
3.	मिश्रित अर्थव्यवस्था ( Mixed Economy )	17
4.	केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध–I ( Centre-State Financial Relations–I )	24
5.	केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध–II ( Centre-State Financial Relations–II )	30

S.No	o. Chapter	Page
6.	राजकोषीय नीति, समता और सामाजिक न्याय ( Fiscal Policy, Equity and Social Justice )	37
7.	सरकारी बजट प्रक्रिया : सिद्धान्त एवं कार्य ( Government Budgeting: Principles and Functions )	44
8.	भारतीय बजट व्यवस्था ( Indian Budgetary System )	50
9.	सरकारी न्याय का वर्गीकरण ( Classification of Government Expenditure )	58
10.	सार्वजनिक व्यय : सिद्धान्त एवं विकास ( Public Expenditure: Theories and Growth )	63
11.	निष्पादन बजट प्रणाली ( Performance Budgeting )	69
12.	शून्य-आधारित बजट प्रणाली (Zero-Base Budgeting)	75
13.	राजस्व के स्रोत : कर एवं करों के अतिरिक्त आय (Resources of Revenue: Tax and Non-tax Income )	82
14.	घाटे का वित्तीयन ( Deficit Financing )	87
15.	सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका ( Public Debt Management and Role of Reserve Bank of India )	93
16.	वित्तीय मूल्यांकन ( Financial Appraisal )	99
17.	आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यांकन ( Economic and Social Appraisal )	105
18.	विधायी नियंत्रण ( Legislative Control )	111
19.	वित्तीय समितियों की व्यवस्था ( System of Financial Committees )	118

<b>S</b> .N	o. Chapter	Page
20.	कार्यकारी नियंत्रण ( Executive Control )	124
21.	भारत में लेखा-शास्त्र की प्रणाली ( Accounting System in India )	130
22.	भारत में लेखा परीक्षण की प्रणाली ( Auditing System in India )	135
23.	लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की भूमिका ( Role of the Comptroller and Auditor General: CAG )	142
24.	सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय प्रशासन ( Financial Administration of Public Enterprises )	146
25.	सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्वायत्तता एवं जवाबदेही ( Financial Autonomy and Accountability of Public Enterprises )	151
26.	शहरी शासन का वित्तीय प्रशासन ( Financial Administration of Urban Governments )	156
27.	ग्रामीण शासन का वित्तीय प्रशासन ( Financial Administration of Rural Governments )	160



# **QUESTION PAPER**

(June – 2019)

## (Solved)

### वित्तीय प्रशासन

समय : 3 घण्टे ]

[ अधिकतम अंक : 100 ( कुल का 70% )

#### भाग-।

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए– प्रश्न 1. भारत में वित्तीय प्रशासन के कार्यक्षेत्र की चर्चा कीजिए।

**उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-1, पृष्ठ 5, प्रश्न 3

प्रश्न 2. सार्वजनिक व्यय के विभिन्न निर्धारकों का वर्णन कीजिए।

**उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-10, पृष्ठ 63, 'सार्वजनिक व्यय के निर्धारक तत्त्व'

प्रश्न 3. घाटे के वित्तीयन के लाभों और सीमाओं का परीक्षण कीजिए।

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-14, पृष्ठ 90, प्रश्न 2 (अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न)

प्रश्न 4. नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के लेखाओं और लेखा-परीक्षण से संबंधित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों की चर्चा कीजिए।

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-23, पृष्ठ 144, प्रश्न 2

#### भाग–II

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए– प्रश्न 5. राजकोषीय नीति के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

**उत्तर-संदर्भ**-देखें अध्याय-6, पृष्ठ 39, अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न 1

प्रश्न 6. अप्रत्यक्ष करों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर-राज्य के द्वारा खपत, आयात, निर्यात और उत्पादन इत्यादि पर जो कर लगाया जाता है, वह अप्रत्यक्ष कर होता है। आय और सम्पति पर जो कर लगाया जाता है, वह प्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर को सीधे अर्जक की आय या नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये आय कर की तुलना में कम स्पष्ट हैं। इनको किसी भी पर्ची पर नहीं दिखाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर मध्यस्थों के माध्यम से एकत्र कराया गया एक ऐसा आर्थिक कर है. जिसमें उपभोक्ता पर आर्थिक कर का भार आता है और जिसको रिटेल स्टोर वाले या मध्यस्थ एक टैक्स रिटर्न दाखिल कर सरकार को इसका भुगतान करते है। उत्पादों की कीमत को बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर एक स्थानान्तरित कर है।

अप्रत्यक्ष कर निर्धारण को राजस्व की वृद्धि के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी भी माल की खरीद के लिए या सेवाओं का आनंद लेने के लिए इस कर का भुगतान अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। यह कर समाज के हर वर्ग पर लागू होता है, यह अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से लगता है। यह कर उनकी आय को देखकर नहीं लगाया जाता। अप्रत्यक्ष कर को प्रतिभागी कर के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है

क्योंकि इस वजह से गरीबों पर बोझ अधिक बढ़ जाता है। अप्रत्यक्ष कर के प्रकार–सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन किया गया है।

1. उत्पाद कर – भारत में जिस वस्तु का निर्माण हो रहा है, उन पर यह कर लगाया जाता है। यह कर निर्माता के द्वारा दिया जाता है जिसे बाद में निर्माता थोक व्यापारियों के कंधे पर डाल देता है।

2. बिक्री कर – जब निर्माता व्यपारियों पर कर का बोझ डालता है तो व्यापारी थोक विक्रेता आदि सामान या सेवाओं पर बिक्री कर चार्ज करके बोझ को ग्राहकों को स्थानांतरित कर देते हैं।

3. सीमा शुल्क ड्यूटी-जब कोई माल एक देश से दूसरे देश में आयात/निर्यात होता है, तो देश के बाहर से आने वाले माल पर आयात शुल्क एवं बाहर जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा किया जाता है।

4. वैट-राज्य सूची के प्रवेश 54 में यह वर्जित है कि काराधान विभागों के माध्यम से राज्य सरकार अपने राज्यों में वैट

2 / NEERAJ : वित्तीय प्रशासन (JUNE-2019)

लगाने के लिए जिम्मेदार है। वैट, वस्तुओं/सेवाओं के उपभोग पर लगने वाला अंतिम कर है, इसलिए अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा इस कर को दिया जाता है।

5. प्रतिभूति विनिमय कर – यह एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में शेयर बाजारों के माध्यम से की गई खरीद/बिक्री के समय लगाया जाता है, जिनमें शामिल है–शेयर, म्यूचुअल फंड, विनिमय आदि।

प्रश्न 7. सार्वजनिक उपक्रम समिति पर एक टिप्पणी लिखिए।

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय–19, पृष्ठ 119, 'सरकारी उपक्रम समिति', 'सरकारी उपक्रम समिति के कार्य'

प्रश्न 8. शहरी स्थानीय वित्त सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-26, पृष्ठ-156, 'शहरी स्थानीय वित्त के सिद्धांत'

प्रश्न 9. विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए।

**उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-9, पृष्ठ 61, प्रश्न 2

प्रश्न 10. भारत में ग्रामीण शासन के राजस्व के स्रोतों पर प्रकाश डालिए।

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-27, पृष्ठ 162, 'अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न 1

प्रश्न 11. भारत में बजट व्यवस्था के क्रमविकास की व्याख्या कीजिए।

**उत्तर-संदर्भ-**देखें अध्याय-8, पृष्ठ 53, अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न 1

प्रश्न 12. वित्तीय प्रशासन के महत्त्व की चर्चा कीजिए। उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ 2, 'वित्तीय प्रशासन का महत्त्व' पृष्ठ 3, प्रश्न 1 और 3

इसे भी देखें-इस प्रकार, वित्तीय प्रशसन के मूल में एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था कार्यरत होती है। एक कल्याणकारी राज्य में यह केवल प्रशासन के नियंत्रण के उपकरण के रूप में ही कार्य नहीं करता अपितु आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि के सशक्त केंद्रों को धन के प्रवाह में नियंत्रण का कार्य करता है। यह कार्यशील अभिकरणों की गतिविधियों में प्राथमिकताओं के निर्धारण में भी साधन का कार्य करता है। राज्य को संतुलन में रखने के लिए सुगठित वित्तीय प्रणाली के अतिरिक्त देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए इसे गति, दिशा तथा प्रारूप के निर्धारण की भी आवश्यकता भी है।

#### भाग–III

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए– प्रश्न 13. "सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण कई तरह

से किया जा सकता है।" चर्चा कीजिए।

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय–15, पृष्ठ 96, अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न 2

प्रश्न 14. वित्तीय स्वायत्ततता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए।

**उत्तर**–स्वायत्तता का साधारण अर्थ निर्णय लेने तथा उसके अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है।

सार्वजनिक उपक्रमों को दी जाने वाली वित्तीय स्वायत्तता का अर्थ है। उन्हें निवेश प्रबंध, निवेश के लिए धन प्राप्त करने एवं सुदृढ़ व्यापारिक सिद्धांतों तथा वित्तीय प्रशासकों की बुद्धिमत्ता पर आधारित निजी उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को नियंत्रित करने के क्षेत्र में अपने-आप निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना। निवेश के संबंध में सार्वजनिक उपक्रमों को परियोजना को पहचानने, परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता, प्रतिवेदन का निर्माण करने, परियोजना का मूल्यांकन करने, निवेश का चुनाव करने व उनके कार्यान्वयन तथा नियंत्रण की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

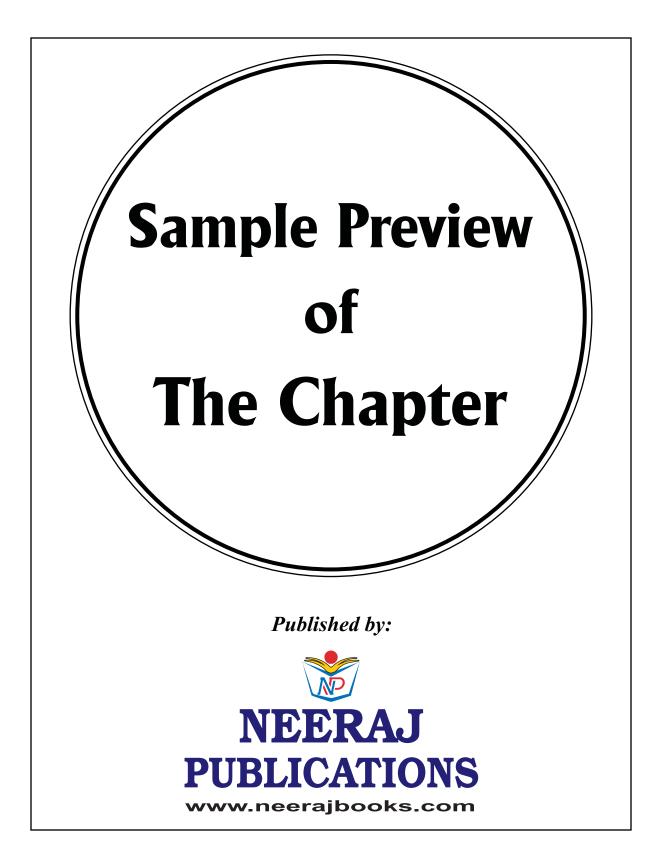
किसी संगठन की वित्तीय स्वायत्तता से कई बाहरी तत्त्व भी संबंधित होते हैं। अन्य शब्दों में, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली इस स्वायत्तता को निर्धारित करती है। वित्तीय स्वायत्तता के छः स्तर होते हैं। ये हैं-संसद, सरकार, भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक, न्यायालय, जन-संचार माध्यम व नागरिक। सार्वजनिक उपक्रमों को दिन-प्रतिदिन के वित्तीय निर्णय निर्माण में स्वायत्तता होनी चाहिए। इनकी परिधि में मुख्यत: जो निर्णय आते हैं, वे हैं-सामान्य क्रय, लागत, आबंटन, योग्य कीमत संरचना का विकास, वित्त के सुयोग्य स्रोतों व सम्मिश्रणों का चुनाव, वित्तीय सूचना व्यवस्था का संस्थापन व संचालन एवं खातों का निर्माण तथा अंतिम रूपकरण।

संदर्भ–देखें अध्याय-25, पृष्ठ 151, 'स्वायत्तता'

प्रश्न 15. लेखाशास्त्र को परिभाषित कीजिए और इसके महत्त्व की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-21, पृष्ठ 130, 'लेखा शास्त्र' प्रश्न 16. आकलन समिति के कार्य क्या हैं? उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-19, पृष्ठ 119, 'आकलन

समिति : समिति के कार्य'



# वित्तीय प्रशासन

# (Financial Administration)

# वित्तीय प्रशासन की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र (Nature and Scope of Financial Administration)

#### अध्याय की विषय-वस्तु

वित्तीय प्रशासन-'वित्तीय प्रशासन' दो अलग-अलग शब्दों से मिलकर बना है। 'वित्त' का अर्थ है धन संसाधन। 'प्रशासन' का अर्थ है जागरूक उद्देश्य की खोज में सामूहिक मानव प्रयास का संगठन तथा प्रबंध। इस प्रकार वित्तीय प्रशासन ऐसे कार्यों का संग्रह है, जो विभिन्न कार्यालयों या संगठनों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धन उपलब्ध कराने से संबंधित है; वह विभाग चाहे रेलवे विभाग हो, कृषि विभाग हो, सड़क यातायात, निगम चिकित्सा, म्युनिसिपल बोर्ड हो या परिवार के दैनिक क्रियाकलाप हों, सब धन की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करते हैं, जिससे वित्तीय प्रशासन संबंधित है। एल.डी. ह्वाइट के अनुसार, "वित्त प्रबन्ध के अन्तर्गत वे क्रियाएँ सम्मिलित हैं जो अधिकारियों को धन उपलब्ध कराती हैं तथा उसका वैधानिक एवं कुशलतापूर्वक प्रयोग करने का आश्वासन देती हैं।"

जेज गैस्टन के अनुसार, "वित्त प्रशासन सरकारी संगठन का वह भाग है जो सार्वजनिक धन के संग्रह, सुरक्षा, आबंटन, सार्वजनिक राजस्व तथा व्यय में समन्वय, राज्य की तरफ से ऋण, क्रियान्वयन का प्रबन्ध, सार्वजनिक घरेलू वित्तीय मामलों के सामान्य नियन्त्रण से संबंधित है।"

जी.एस. लाल के अनुसार, "वित्त प्रशासन राज्य के वित्तीय प्रबन्ध के समस्त पहलुओं से सर्बोधत है, जबकि लोक प्रशासन लोक मामलों तथा लोकहित से अधिक संबद्ध है।"

वित्तीय प्रशासन की व्यापक परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है, "वित्त प्रशासन में वे समस्त क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जो वित्तीय संसाधनों की उत्पत्ति, संचालन तथा विनियोजन करती हैं। ये राजनीतिक समुदाय के सदस्यों के विकास तथा जीवन के लिए आवश्यक होती हैं।"

सार्वजिनक वित्त तथा व्यक्तिगत वित्त में अन्तर

वित्तीय कार्य सार्वजनिक व निजी दोनों संगठनों में समान रूप से पाये जाते हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो नियम तथा सिद्धांत निजी वित्त में लागू होते हैं, वही समान रूप से सार्वजनिक वित्त में भी लागू होंगे। सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में अन्तर पूरी तरह से स्पष्ट है।

**के.पी.एम. सुन्दरम्** के अनुसार इन्हें निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है :

#### 2 / NEERAJ : वित्तीय प्रशासन

व्यक्तिगत वित्त	सार्वजनिक वित्त		
1. व्यय का आय के साथ	1. आय का व्यय के साथ		
सामंजस्य	सामंजस्य		
(अ) सरकारी नियंत्रण	(अ) लोकप्रिय नियंत्रण		
2. सीमित संसाधन	2. लचीले संसाधन		
3. शक्ति का अभाव	3. दमनकारी शक्ति द्वारा		
	संसाधनों का प्रयोग		
4. सन्तुलित बजट की प्रवृत्ति	4. घाटे की प्रवृत्ति		
5. लाभ में अधिकाधिक वृद्धि	5. लोक सेवा की तरफ व्यय		
	की दिशा		

#### वित्तीय प्रशासन का महत्त्व

औद्योगिक क्षेत्र में आई क्रान्ति के समय तक वित्त प्रशासन के महत्त्व को नहीं समझा गया था। सरकार की संकल्पना अबन्ध सिद्धांत के एक भाग के रूप में कम से कम कर लगाए जाने के पक्ष में थी। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् जब सामाजिक जीवन जटिल हो गया, तो सरकार की भूमिका अधिक व्यापक हो गई। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ने राज्य के कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वृद्धि की। सरकार ने अब उन क्षेत्रों में प्रवेश किया जो राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर रखे गए थे। इस तरीके से बदलते हुए सन्दर्भ में वित्त प्रशासन ने बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों की उत्पत्ति के नए तरीकों तथा साधनों को ढूंढने से अधिक महत्ता प्राप्त की।

#### वित्तीय प्रशासन की प्रकृत्ति

वित्तीय प्रशासन की प्रकृति के दो भिन्न दृष्टिकोण हैं :

1. परम्परागत दुष्टिकोण, 2. आधुनिक दुष्टिकोण

1. परम्परागत दृष्टिकोण-इस दृष्टिकोण के अनुसार वित्त प्रशासन उत्पत्ति, विनियोजन तथा वित्तीय संसाधनों की खोज से सम्पादित क्रियाओं का योग है, जो लोक संगठनों को जीवित रखने तथा उनके विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी भी लोक प्रशासन में एक प्रशासनिक ढाँचा होता है, जो धन के आवागमन को व्यवस्थित करने के साथ-साथ इसे नियंत्रित और व्यवस्थित भी करता है। इस व्यवस्था के कारण ही इन कोषों का सही और उत्पादक उपयोग संभव हो पाता है। व्यवस्थाओं के संदर्भ में इस दृष्टिकोण पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सहभागिता व्यवस्था का एक रूप है।

2. आधुनिक दृष्टिकोण–आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय प्रशासन को सार्वजनिक निधि बढ़ाने तथा व्यय करने के साधन की बजाय लोक संगठनों की सम्पूर्ण प्रबन्धकीय प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माना जाता है। इसके अनुसार लोक प्रशासन में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की समस्त क्रियाएं आती हैं। यह परम्परागत सिद्धांत के मूल्य तटस्थता के दृष्टिकोण को नकारता है। इसमें सार्वजनिक वित्त के तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल किया जाता है; जैसे–आर्थिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत तथा आधुनिक सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञों के कार्यात्मक दूष्टिकोण।

#### वित्त प्रशासन की भूमिका

समानता लाने वाली भूमिका

- 2. प्रकार्यात्मक भूमिका
- 3. कार्यात्मक भूमिका
- 4. स्थायित्व संबंधी भूमिका
- 5. सहभागी भूमिका।
- वित्त प्रशासन का कार्यक्षेत्र

वित्त प्रशासन के कार्यक्षेत्र में मुख्यत: निम्नलिखित कार्य आते हैं :

1. लोक निधियों का संग्रह, रक्षा तथा आबंटन

2. लोक राजस्वों तथा व्यय का समन्वय

3. राज्य की तरफ से ऋण संचालन का प्रबंध

4. सरकार के वित्तीय मामलों का सामान्य नियन्त्रण।

लोक प्रशासन के कुछ विशेषज्ञों के अनुसार वित्त प्रशासन विधायी वित्त नियंत्रण में सन्निहित वित्त प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं को दर्शाता है। उनके विचार के अनुसार वित्त प्रशासन के कार्यक्षेत्र में अनुमानों की तैयारी, निधियों का विनियोजन, व्यय नियंत्रण, लेखांकन, लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन, समीक्षा आदि शामिल हैं।

दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय प्रशासन के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए बजट अनिवार्य है। इसके अनुसार वित्त प्रशासन का कार्यक्षेत्र बजट की तैयारी, बजट बनाना तथा बजट निष्पादन तक ही सीमित है।

इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार वित्तीय प्रशासन के निम्नलिखित पहलू घनिष्ठ रूप से उभरते हैं :

(i) वित्तीय नियोजन-इसका उद्देश्य है सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन को बढ़ाना। लेकिन विस्तृत अर्थ में नियोजन सरकारी नीतियों के सम्पूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है।

(ii) बजट बनाना-यह वित्त प्रशासन का आधार है। यह महत्त्वपूर्ण पहलुओं; जैसे-राजकोषीय नीति, समानता तथा सामाजिक न्याय जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों का निर्धारण तथा परीक्षण करता है।

(iii) संसाधनों का संघटन-इस क्षेत्र के अन्तर्गत करों का आरोपण, दरों तथा करों का संग्रह आदि आते हैं। सरकार की बढ़ती वचनबद्धता के कारण बजट संबंधी घाटा सरकारी वित्त की एक सामान्य विशेषता बन गई है। सार्वजनिक ऋण भी राज्य संसाधन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

(iv) निवेश संबंधी निर्णय-पूँजीगत व्यय के वित्तीय तथा सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन को परियोजना मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी पूँजी लगायी जा रही है। अत: वित्तीय प्रशासकों को परियोजना मूल्यांकन की संकल्पना, तकनीक तथा पद्धति से पूरी तरह अवगत होना चाहिए।

(v) व्यय नियंत्रण–आधुनिक सरकारों की वित्तीय व्यवस्था को जरूरत से ज्यादा नहीं फैलाया जा सकता है। प्रत्येक सरकार संसाधनों की कमी से ग्रस्त है। अत: संसाधनों को सावधानीपूर्वक उपयोग में लाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(vi) लेखांकन, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण—कार्यपालिका नियंत्रण तथा विधायी नियंत्रण दोनों को सहायता देने के लिए इन पहलुओं की व्यवस्था की गई है। लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि लेखा तथा लेखा परीक्षण संबंधी कार्यों को संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सम्पादित किया गया है या नहीं।

(vii) वित्त प्रशासन के अवयव—सार्वजनिक वित्त के विशेषज्ञों के अनुसार वित्त प्रशासन के तीन अवयवों का उल्लेख किया गया है :

- (अ) सार्वजनिक राजस्व (ब) सार्वजनिक व्यय
- (स) सार्वजनिक ऋण।

वित्त प्रशासन लोक वित्त से संबंधित है तथा राज्य वित्त के उपयुक्त तथा कुशल प्रशासन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों को दर्शाता है, अत: वित्त प्रशासन के चिन्तकों ने वित्त प्रशासन के कार्यक्षेत्र में प्रशासकीय पहलुओं को भी सम्मिलित किया है।

#### (बोध प्रश्न-1)

प्रश्न 1. वित्तीय प्रशासन के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उत्तर–

- (i) वित्तीय प्रशासन का शाब्दिक अर्थ क्रियाओं का संग्रह है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों या संगठनों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धन उपलब्ध कराने से संबंधित है।
- (ii) वित्तीय कार्य प्रबन्धकीय प्रक्रिया के रूप में होते हैं।
- (iii) वित्तीय प्रशासन में सरकार का वित्तीय कार्य भी आता है।
- (iv) वस्तुत: वित्त महत्त्वपूर्ण होता है, जो सामाजिक प्रक्रिया
   में भाग लेता है।

प्रश्न 2. सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में अन्तर बताते हुए तीन बातें (Points) लिखिये।

#### उत्तर–

_			
(	सार्वजनिक वित्त		निजी वित्त
(i)	आय का व्यय के साथ	(i)	व्यय का आय के साथ
	सामंजस्य होता है, परन्तु		सामंजस्य होता है और
	इस पर लोकप्रिय नियंत्रण		इस पर सरकारी
	होता है।		नियंत्रण होता है।
(ii)	इसके संसाधन लचीले	(ii)	इसके संसाधन सीमित
	होते हैं।		होते हैं।
(iii)	इसमें दमनकारी शक्ति	(iii)	इसमें दमनकारी शक्ति
	द्वारा संसाधनों का उपयोग		का अभाव होता है।
	किया जाता है।		
(iv)	इसमें घाटे की प्रवृत्ति	(iv)	इसमें संतुलित बजट
	होती है।		की प्रवृत्ति होती है।
(v)	इसमें खर्च की दिशा लोक	(v)	इसमें लाभ की संभावना
Ú	सेवा की ओर होती है।		होती है।

वित्तीय प्रशासन की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र/3

प्रश्न 3. वित्तीय प्रशासन का अध्ययन वर्तमान समय में क्यों महत्त्वपूर्ण हो गया है?

**उत्तर**—वित्तीय प्रशासन का अध्ययन वर्तमान समय में निम्नलिखित कारणों से महत्त्वपूर्ण है :

- (i) वित्त प्रशासन में बजट संबंधी सुधारों की सम्भावना होती है।
- (ii) वित्त प्रशासन संकल्पना निधियों के संवितरण पर नियंत्रण से विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों
   में परिवर्तित होती है।
- (iii) वित्त प्रशासन में बेकार के खर्चों को समाप्त करने तथा सीमित संसाधनों के आधार पर उत्पाद बढ़ाने पर बल दिया जाता है, जिससे विकास होता है।
- (iv) वित्त प्रशासन लोकप्रिय सम्प्रभुता को एक सामाजिक यथार्थ या वास्तविकता स्थापित करने में आधुनिक सरकार की सहायता करता है।

#### (बोध प्रश्न-2)

प्रश्न 1. परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय प्रशासन की क्या भूमिका है?

उत्तर—परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय प्रशासन की निम्नलिखित भूमिका है :

- (i) यह एक प्रकार का संचालित उपकरण है।
- (ii) इसमें मूल्य तटस्थ दृष्टिकोण होता है।
- (iii) इसमें निधियों के प्रवाह की व्यवस्था होती है।
- *(iv)* यह एक व्यवस्था है।

्रप्रश्न 2. आधुनिक सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञों द्वारा प्रतिपादित वित्त प्रशासन की दो भूमिकाओं का विवेचन कीजिए।

**उत्तर**—आधुनिक सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञों द्वारा प्रतिपादित वित्त की दो प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं :

(i) यह समानता लाने में सहायक है।

(ii) यह वित्त की वृद्धि करने में सहायता करती है।

प्रश्न 3. वित्तीय प्रक्रियायें क्या हैं तथा विधायी वित्तीय नियंत्रण में कौन-सी संस्थायें सम्मिलित होती हैं?

उत्तर—वित्तीय प्रक्रिया में अनुमानों की तैयारी, निधियों का विनियोजन, व्यय नियंत्रण, लेखांकन, लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन, समीक्षा आदि शामिल हैं।

प्रश्न 4. वित्त प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में विस्तृत या व्यापक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।

**उत्तर**–प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में विस्तृत या व्यापक दृष्टिकोण में निम्नलिखित बातें आती हैं :

#### 4 / NEERAJ : वित्तीय प्रशासन

- (i) वित्तीय नियोजन
- *(ii)* बजट संघटन
- (iii) संसाधन जुटाना
- (iv) निवेश संबंधी निर्णय
- (v) व्यय नियंत्रण
- (vi) लेखांकन तथा लेखा परीक्षण।

### (बोध प्रश्न−3)

प्रश्न 1. पोस्डकोर्स दृष्टिकोण (POSDCORC view) के अनुसार वित्त प्रशासन के मुख्य तत्त्व क्या हैं? उत्तर–पोस्डकोर्स दुष्टिकोण के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित

#### हें :

- (i) वित्तीय नियोजन
- (ii) वित्तीय संगठन
- (iii) वित्तीय कर्मचारीगण
- (iv) वित्तीय सुझाव या परामर्श
- (v) आय तथा व्यय में समन्वय
- (vi) कार्यपालिका, विधायिका तथा लेखा परीक्षण द्वारा नियंत्रण।

```
प्रश्न 2. वित्तीय प्रशासन के तत्त्वों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर–वित्तीय प्रशासन के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं :
```

- I. मानव तत्त्व
- *(i)* करदाता
- *(ii)* शुल्क अदाकर्त्ता
- (iii) आपूर्तिकर्त्ता (धन तथा पदार्थ)
- *(iv)* नौकरी-पेशा (लोक अधिकारी)
- (v) उद्यमी (राजनीतिज्ञ)
- (vi) ग्राहक तथा साधारण व्यक्ति
- II. कार्य तथा संरचना
- (i) व्यवस्थापिका तथा इसको वित्तीय समितियां
- (ii) केबिनेट या मंत्रिमंडल
- (iii) वित्त विभाग
- (iv) प्रशासकीय विभाग
- (v) कार्यपालिका विभाग
- (vi) लेखा परीक्षा विभाग

#### III. व्यवस्था एवं कार्यविधि

- *(i)* नियोजन व्यवस्था
- (ii) बजट बनाने की प्रक्रिया
- (iii) लेखांकन तथा लेखा परीक्षण जैसी नियंत्रण व्यवस्था।

#### अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. वित्त प्रशासन को परिभाषित कीजिए।

उत्तर-वित्त प्रशासन की परिभाषायें-वित्त प्रशासन कार्यों का वह समूह है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यालयों या संगठनों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धन उपलब्ध कराने से सम्बंधित है। कृषि विभाग, रेलवे, सड़क, यातायात, निगम, शिक्षा विभाग, प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र आदि सबमें धन की आवश्यकता होती है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों की परिभाषायें निम्नलिखित हैं:

- (i) एल.डी. ह्वाइट के अनुसार, "वित्त प्रबंध के अन्तर्गत वे क्रियायें सम्मिलित हैं, जो अधिकारियों को धन उपलब्ध कराती हैं तथा उसका वैधानिक एवं कुशलतापूर्वक प्रयोग करने का आश्वासन देती हैं।"
- (ii) जेज गैस्टन के अनुसार, "वित्त प्रशासन सरकारी संगठन का वह भाग है, जो सार्वजनिक धन से संग्रह, सुरक्षा एवं आबंटन, सार्वजनिक राजस्व तथा व्यय में समन्वय, राज्य की ओर से ऋण, क्रियान्वयन के प्रबन्ध, सार्वजनिक घरेलू वित्त मामलों के सामान्य नियंत्रण से संबंधित है।"
- (iii) जी.एस. लाल के अनुसार, "वित्त प्रशासन राज्य के वित्तीय प्रशासन, राज्य के वित्तीय प्रबन्ध के समस्त पहलुओं से संबंधित है, जबकि लोक प्रशासन लोक मामलों तथा लोकहित से अधिक संबद्ध है।"

प्रश्न 2. वित्तीय प्रशासन की प्रकृति की विवेचना कीजिए।

#### अथवा

परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय प्रशासन की भूमिका बताइए।

#### अथवा

आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय प्रशासन की भमिका क्या है?

उत्तर-वित्तीय प्रशासन की प्रकृति-वित्तीय प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं :

I. परम्परागत दृष्टिकोण

II. आधुनिक दृष्टिकोण

I. परम्परागत दृष्टिकोण-परम्परागत दृष्टिकोण में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

> (i) इसके अनुसार वित्त प्रशासन उत्पत्ति, विनियोजन तथा वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की क्रियाओं का संग्रह है, जो संगठनों को जीवित रखने तथा उनके विकास के लिए आवश्यक होती हैं।